पंजाब सरकार

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री, पंजाब

द्वारा

पंजाब विधान सभा में

वर्ष 2024-25 का

बजट पेश करते समय दिया गया

भाषण

5 मार्च, 2024

चण्डीगढ़

बजट 2024-25

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री

का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. सम्मान और जिम्मेदारी की अथाह भावना के साथ, मैं पिछले दो वर्षों की यात्रा पर विचार करने और माननीय मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के गतिशील नेतृत्व में आप सरकार के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का बजट पेश करने के लिए इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष खड़ा हूं।

2. विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विपरीत परिस्थितियों में लचीले दृष्टिकोण और लोगों के हितों की सेवा के लिए हमारा समर्पण हमारे सामूहिक प्रयासों के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। आज, जब हम अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने, महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले भविष्य को प्रोत्साहित के दृढ़ संकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण तीसरे वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं जनाब बशीर बदर की दो पंक्तिया कहना चाहूंगा -

जिस दिन से चला हूँ मिरि मंज़िल पे नज़र है

आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा ।

3. जैसा कि अतीत में आप सरकार ने वादा किया था, हम राज्य के राजस्व को समेकित करने में सक्षम रहे हैं। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर 2012-17 के दौरान 8% और 2017-22 के दौरान 6% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में

काफ़ी अधिक यानी 13% रही है। । इससे पता चलता है कि पेशकारी विचारों की स्पष्टता और सोच को कार्यों में बदलने के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करती है।

4. हमारी सरकार ने "रंगला पंजाब" का वादा किया था और सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आप सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। "भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार", "राशन की डोर स्टेप डिलीवरी" और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय जैसी पहलकदमियां एक कुशल और प्रभावी प्रशासन बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसी प्रकार "आप की सरकार आप दे द्वार" लॉन्च किया गया है, जिससे गांवों में कैम्प आयोजित कर के 8 लाख से अधिक नागरिकों को सेवाएं प्रदान की गई हैं।

5. हमारी नीतियां फलीभूत होने लगी हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस अब एक वास्तविकता है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने के हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आम आदमी क्लिनिक की स्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किसी क्रांति से कम नहीं है। ये क्लीनिक आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण, किफ़ायती और मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस पहल को विधिवत मान्यता दी गई है और पंजाब को नैरोबी, केन्या में आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन-2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

6. हमारी सरकार के ठोस प्रयासों और निश्चित कार्यों के माध्यम से पंजाब के युवाओं को रोजगार के अनगिनत अवसर मिले हैं। हम युवा पंजाबियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार ने इन दो वर्षों के दौरान योग्य युवाओं को 40,437 नौकरियां प्रदान की हैं। अर्थात प्रति दिन 55 से अधिक नौकरियाँ दी गईं हैं।

7. मुझे संतोष है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का खेतों के अंतिम छोर तक नहर का पानी पहुंचाने का सपना साकार हुआ। यह निश्चित रूप से हमारी कृषि, हमारे घटते जलस्तर के लिए परिवर्तनकारी कदम साबित होगा और पंजाब को 'रेगिस्तान' बनने से बचाएगा। इस संबंध में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और हमारी सरकार द्वारा बहुत कुछ किया भी जाएगा।

8. यह उन लाभों को समेकित करने का वर्ष है जो पिछले दो वर्षों में हासिल किए गए हैं। यह समय हमारी सरकार द्वारा बोए गए विकास के पौधों को पोषित करने का है, ताकि वे फलीभूत होकर हमारी भावी पीढ़ियों को लाभ पहुंचा सकें।

9. यहां मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पंजाब के प्रति केंद्र सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता के बारे में इस सम्मानित सदन को अवगत करवाऊं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम), ग्रामीण विकास निधि (आर.डी.एफ), मंडी विकास निधि (एम.डी.एफ) और पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के मद में राज्य का लगभग 8,000 करोड़ रुपये के उचित हिस्से को रोके जाने का सीधा असर हमारे विकासात्मक कार्यों पर पड़ा है और राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला है।

बजट वित्तीय वर्ष 2024-25

माननीय अध्यक्ष महोदय,

10. डायरैक्टोरेट आफ़ स्टैटिसटिक्स द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, पंजाब चालू वर्ष में 9.41% की दर से बढ़ रहा है और जीएसडीपी 7,36,423 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी 9% बढ़कर 8,02,701 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

11. लगातार दूसरे वर्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि से आप सरकार की ईमानदारी और समर्पण एक बार आप सब के सामने है। चालू वर्ष में जनवरी तक पंजाब का अपना कर राजस्व 12% बढ़ गया है।

12. मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,04,918 करोड़ रुपये के कुल बजट व्यय का प्रस्ताव रखता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.77% और 3.80% होने की उम्मीद है और क्रमशः 3.13% और 4.12% के पिछले आंकड़े से सुधार हुआ है।

13. अब, मैं वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय बजटीय आवंटन के साथ विकास रोडमैप की रूपरेखा आप के समक्ष रखूंगा।

कृषि एवं किसान कल्याण

अध्यक्ष महोदय,

14. अगले वित्तीय वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 13,784 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।

फसल विविधीकरण

15. अध्यक्ष महोदय, हम केवल बातें करने में विश्वास नहीं करते हैं, हम कार्रवाई में विश्वास करते हैं, और मैं विभिन्न फसल विविधीकरण योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 575 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मेहनती किसानों को विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहें और इस प्रकार आप सरकार भविष्य में भी ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी। हमारी कृषि, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे गिरते जलस्तर को सुधारना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

16. चालू वर्ष में किसानों को कपास की उचित खेती के लिए समय पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष "मिशन उन्नत किसान" शुरू किया गया है। हमारी सरकार ने लगभग 87,000 किसानों को कपास के बीज पर 33% सब्सिडी भी प्रदान की है।

17. हम समझते हैं कि मूल्यवर्धन के बिना विविधीकरण के माध्यम से कृषि में सुधार से वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए पैग्रेक्सको को चालू वर्ष में पहले ही प्राजैक्ट शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। होशियारपुर में स्वचालित बीवरेज युनिट की स्थापना; मिर्च प्रोसेसिंग केंद्र, अबोहर; मूल्य वर्धित प्रोसेसिंग सुविधा, जालंधर; फतेहगढ़ साहिब में रेडी टू ईट फूड मैनुफ़ैक्चरिंरिंग युनिट और के अन्य प्राजैक्टों के लिए 250 करोड़ रुपये का सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बागवानी

18. ऊपर बताए गए विभिन्न फसल विविधीकरण उपायों के अलावा, मुझे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बागवानी फसल क्लस्टरों को विकसित करने के लिए नई पहल, यानी पंजाब बागवानी उन्नति और सतत उद्यमिता (फ़ेज़) की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसके लिए बजट में उपयुक्त आवंटन किया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मशरूम खेती की विकास योजनाओं के लिए; फूल बीज उत्पादन के लिए; विदेशी सब्जियों और फलों के बागानों के लिए यह आवंटन किए गए हैं।

किसानों को मुफ्त बिजली

19. हमारी सरकार हर तरह से हमारे "अन्नदाताओं" के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए निरंतर सहायता के रूप में, हमने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के लिए 9,330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मिट्टी एवं जल संरक्षण

अध्यक्ष महोदय,

20. हम सभी अपनी घटती भूजल समस्या से अवगत हैं, 150 में से 114 ब्लॉकों को पहले ही डार्क ज़ोन घोषित किया जा चुका है। उपलब्ध सतही और भूजल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रभावी प्रबंधन के लिए, विभिन्न जल संरक्षण तकनीकों जैसे सूक्ष्म सिंचाई और खेतों में भूमिगत पाइपलाइनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और 13,016 हेक्टेयर क्षेत्र इससे लाभान्वित हुआ है। मैं मिट्टी और जल संरक्षण के लिए 194 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दो नए नाबार्ड प्राजैक्ट शुरू करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन

21. पशुपालन और डेयरी विकास के बिना विविधीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि वे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीनी स्तर पर विशेष पशु चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने और प्रदान करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 326 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 503 पशु चिकित्सा इंस्पैक्टरों की नियुक्ति की है।

22. गांव किल्लियां वाली ज़िला फाजिल्का में एक नया मछली बीज फार्म आरंभ किया गया है। 3,233 एकड़ क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत लाया गया है। एक नदी मछली पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके तहत नदी निकायों में 3 लाख मछली के बीज डाले गए हैं।

सहकारिता

अध्यक्ष महोदय,

23. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली द्वारा ग्रामीण स्तर के कारीगरों को नवीनतम शिल्प कौशल तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने और उन्हें विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए "मिशन फुलकारी" शुरू किया गया है।

24. हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वेरका लुधियाना डेयरी में एक नई सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसमें ताजा दूध और फ़र्मेंटिड उत्पादों के लिए स्वचालित दूध रिसेप्शन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग क्षमताएं शामिल हैं। प्लांट की दैनिक दूध प्रसंस्करण क्षमता 9 लाख लीटर है और यह प्रति दिन 10 मीट्रिक टन मक्खन रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, वेरका फिरोजपुर डेयरी में एक तरल दूध प्रोसेसिंग और पैकेजिंग युनिट और वेरका जालंधर डेयरी में फ़र्मेंटिड उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए एक नए आटोमैटिक युनिट का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है।

25. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष के दौरान गन्ना किसानों को 467 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और इस संबंध में वित्त वर्ष 2024-25 में 390 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

26. शुगरफेड ने भोगपुर सहकारी चीनी मिल में धान की पराली के माध्यम से संचालित अपना पहला 14 मेगावाट का को-जेन प्लांट शुरू किया है और गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल में एक नया इथेनॉल प्राजैक्ट जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 24 करोड़ रुपये की शुरूआती बजटीय सहायता दी गई है।

27. संचालन को आधुनिक बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राइमरी कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

वानिकी एवं वन्य जीवन

28. चालू वर्ष के दौरान पनकैम्पा, ग्रीन पंजाब मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 5,735 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 46.20 लाख पौधे लगाए गए हैं। वन्यजीव शमन उपायों को लागू करने की दृष्टि से, वित्त वर्ष 2024-25 में शमन गतिविधियों के लिए "मानव वन्यजीव संघर्ष शमन योजना की स्थापना" नामक एक नए प्राजैक्ट को शुरू करने का प्रस्ताव है।

29. वानिकी प्रयासों को सहायता देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 263 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है।

शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

30. आप सरकार का लक्ष्य "साक्षर पंजाब" ही नहीं, बल्कि "शिक्षित पंजाब" भी है। हम अपने बच्चों में केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता ही नहीं विकसित करना चाहते, अपितु उनमें ज्ञान, नैतिकता और संवेदनशीलता भी पैदा करना चाहते हैं। अन्य कार्यों के साथ-साथ 12,316 शिक्षकों को रेगुलर करना, 9,518 शिक्षकों की भर्ती, प्रिंसीपलों और हेड-मास्टरों का कौशल उन्नयन, स्कूलों में सुरक्षा उपायों में सुधार, 12,000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन लगाना, स्कूलों में लगभग 4,300 शौचालयों की मरम्मत करवाना और हमारे छात्रों को समय पर पुस्तकें देना हमारी प्राप्तियां रहीं हैं।

31. हमारी सरकार शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने और इसे वर्तमान आर्थिक परिवेश की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 16,987 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं जो कुल व्यय का लगभग 11.5% है।

स्कूल शिक्षा

32. हमारी सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में चारदीवारी के निर्माण और मरम्मत के लिए एक विशेष बुनियादी ढांचा कार्यक्रम शुरू किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2,563 स्कूलों में चारदीवारी का निर्माण किया गया है और 3,055 स्कूलों में चारदीवारी की मरम्मत की गई है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस

33. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 118 सरकारी स्कूल अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तित किए जायेंगे और अब तक 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

स्कूल ऑफ ब्रिलियंस

34. हमारी सरकार 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को "स्कूल ऑफ ब्रिलियंस" के रूप में बदलने का प्रस्ताव रखती है। शुरुआत के लिए, इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इन ग्रामीण स्कूलों को कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग

35. इसके अलावा, छात्रों में तकनीकी कौशल सहित हुनर विकसित करने, उन्हें आजीविका कमाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, हम वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान के साथ "स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग" स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। पहले चरण में 40 स्कूलों में हाईटेक वोकेशनल लैब स्थापित की जाएंगी।

स्कूल ऑफ हैप्पीनेस

36. 3 से 11 वर्ष की आयु के युवा छात्रों के लिए एक बेहतर सीखने का माहौल बनाने के उद्देश्य से, हम 100 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को " स्कूल ऑफ हैप्पीनेस " में बदलने का प्रस्ताव करते हैं। अच्छी हवादार कक्षाएँ, समर्पित खेल क्षेत्र, रिसोर्स रूम और एक्टिविटी कार्नर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्राजैक्ट की शुरुआत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मिशन समरथ

37. हमारी सरकार ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी छात्रों की शिक्षा की बुनियाद को मज़बूत करने के लिए "मिशन समरथ" शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना की शुरुआत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

38. उपरोक्त पहलों के अलावा, हमारी सरकार मौजूदा शैक्षिक योजनाओं को सहायता देना जारी रखेगी। प्रस्तावित आवंटन निम्नानुसार हैं:

i. समग्र शिक्षा अभियान: 1,593 करोड़ रुपये;

ii. 16.35 लाख छात्रों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिए: 467 करोड़ रुपये;

iii. मुफ़्त किताबों, स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए: 140 करोड़ रुपये;

iv. सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन और छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए: 160 करोड़ रुपये;

v. सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता: 82 करोड़ रुपये;

vi. प्री-प्राइमरी छात्रों को वर्दी प्रदान करने के लिए: 35 करोड़ रुपये; और

vii. पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम: 15 करोड़ रुपये।

उच्च शिक्षा

39. आप सरकार समझती है कि उच्च शिक्षा आज न केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में है, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और नए युग की दुनिया के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के बारे में भी है। हमारी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित आवंटन का प्रस्ताव रखती है:

i. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा): 80 करोड़ रुपये;

ii. बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए; खेल सुविधाओं; पुस्तकालय; स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम- 10 करोड़ रुपये;

iii. विश्वविद्यालय फ़ीस में रियायत के लिए सीएम छात्रवृत्ति- 6 करोड़ रुपये; और

iv. सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए- 5 करोड़ रुपये।

तकनीकी शिक्षा

40. पंजाब सरकार विकास के उत्प्रेरक के रूप में तकनीकी शिक्षा के महत्व को पहचानती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मोर्चों पर ठोस प्रयास किए गए हैं ताकि तकनीकी शिक्षा प्रणाली उद्योग की मांगों और विशिष्टताओं के अनुरूप हो।

41. मैं बताना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सह-शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे दाखिले में वृद्धि हुई है और बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग की सुविधा मिल रही है। प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के तहत, 180 एमओयू चालू हैं और 2,760 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय मांग के आधार पर मौजूदा पॉलिटेक्निक में अतिरिक्त कोर्स शुरू किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग के भविष्य के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 525 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

42. अत्यंत खुशी के साथ, मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में 114 करोड़ रुपये की लागत से राज्य कैंसर संस्थान और 45 करोड़ रुपये की लागत से फाजिल्का में तृतीयक कैंसर केंद्र का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर में "सीएम दी योगशाला" भी स्थापित की गई है।

43. हमारी सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार, एसएएस नगर (मोहाली) में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज का काम पूरा हो चुका है और इसने ओपीडी सेवाएं प्रदान करना शुरू भी कर दिया है। इस विशेष संस्थान में डॉक्टरों, नर्सों, और सहायक कर्मचारियों की एक मजबूत टीम के साथ बेजोड़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

44. बर्न यूनिट का निर्माण; सीनीयर-जूनीयर डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास; और सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला में कुल 110 करोड़ रुपये की लागत से एक खेल परिसर बनाया जा रहा है। इसके अलावा, मस्तुआना साहिब; संगरूर,

कपूरथला, मलेरकोटला और होशियारपुर में प्रत्येक 100 एमबीबीएस सीटों वाले मेडिकल कॉलेज पर काम वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू होने की उम्मीद है।

45. मैं चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के तहत विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1,133 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, पटियाला में लड़कियों के छात्रावास बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालयों एवं घटक कालेजों को सहायता अनुदान

46. आप सरकार विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों जैसे जीएडीवीएएसयू, पीएयू, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, जीएनडीयू और अन्य को उनके घटक कॉलेजों के साथ समर्थन देना जारी रखेगी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1425 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है।

47. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के महत्व को समझती है, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा पीएयू को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निभाई गई भूमिका की मान्यता में, वित्त वर्ष 2024-25 में विश्वविद्यालय में अनुसंधान-संबंधित और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में छात्रावास के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 40 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा सेवाएँ

48. जैसा कि हमारे पिछले बजट में वादा किया गया था, हमने नई खेल नीति अधिसूचित की है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार

राशि में काफी वृद्धि की गई है। पंजाब की खेल भावना को फिर से खोजने के लिए "खेडां वतन पंजाब दियां" कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, चालू वर्ष में, लगभग 14,728 खिलाड़ियों को 54 करोड़ रुपये की राशि के पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ग्यारह (11) खिलाड़ियों को नौकरियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें से चार (4) को पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) में और सात (7) को पंजाब पुलिस सेवा (पीपीएस) में नियुक्त किया गया है।

49. आप सरकार ने राज्य के प्रत्येक 180 उत्कृष्ट खिलाड़ियों और उभरते खिलाड़ियों को वजीफा दोगुना कर क्रमशः 16,000/- रुपये और 12,000/- रुपये प्रति माह कर दिया है। मैं पंजाब से खेलों में विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को तैयार करने और पोषित करने की आशा के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में खेल और युवा सेवाओं के लिए 272 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं।

खेल नर्सरी

50. हम पंजाब के सभी जिलों में 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 60,000 खिलाड़ियों के लिए 1,000 खेल नर्सरियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। पहले चरण में, खिलाड़ियों को उचित कोचिंग और खेल उपकरणों की उपलब्धता के साथ 250 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक परिव्यय प्रस्तावित है।

महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय

51. खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, कोचिंग आदि क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

स्वास्थ्य

अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है-

" स्वास्थ्य है तो आशा है और आशा है तो सब कुछ है"

52. पिछले दो वर्षों में, हमारी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों की भलाई के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल लागू कर रही है। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 5,264 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

आम आदमी क्लीनिक

53. राज्य में कुल 829 आम आदमी क्लिनिक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और कई आम आदमी क्लिनिक प्रक्रिया में हैं। इन क्लीनिकों पर 80 प्रकार की दवाएं और 38 डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 01 करोड़ से अधिक मरीज उपचार का लाभ उठा चुके हैं तथा 31 लाख से अधिक डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट किये जा चुके हैं। इस क्रांतिकारी पहल को और मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 249 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।

फरिश्ते

54. हमारी सरकार ने किए गए वायदे के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में लगी चोटों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने और उपलब्ध सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में तत्काल, परेशानी मुक्त उपचार प्रदान करने के इरादे से फरिश्ते योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, आम लोगों को आगे आकर दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और पीड़ितों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे 'फ़रिश्तों' को नकद पुरस्कार, प्रशंसा प्रमाण

पत्र दिया जाएगा और कानूनी जटिलताओं और पुलिस पूछताछ से प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 20 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजटीय आवंटन प्रस्तावित है।

आयुष्मान भारत- मुख मंत्री सरबत सेहत बीमा योजना

55. इस योजना के तहत कुल 44.10 लाख परिवारों में से 35.59 लाख परिवारों के लिए ई-कार्ड बनाए गए हैं और 207 सार्वजनिक और 570 निजी और 6 भारत सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से इलाज पर लगभग 2,227 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 553 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।.

नशा मुक्ति

56. राज्य सरकार राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करने और असहाय नशेड़ियों को सामान्य स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल 529 ओओएटी क्लीनिकों और 306 पुनर्वास केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से एक व्यापक नशा मुक्ति योजना लागू की गई है। इसके अलावा, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श/राय देने करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (आईएमएच), अमृतसर में एक टेली मानस हब स्थापित किया जा रहा है। मैं इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित रखता हूं।

पंजाब शहरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा

57. मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान में 3 जिला अस्पतालों - लुधियाना; संगरूर और जालंधर में अपग्रेडेशन के कार्य किए जा रहे हैं। मैं शेष 20 जिला अस्पतालों में क्रमिक तरीके से विभिन्न बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन के

लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

58. उपरोक्त के अलावा, पीआईडीबी के माध्यम से चीमा, कौरीआं, धूरी (संगरूर) और एसएएस नगर (मोहाली) में ग्रामीण अस्पताल और उपमंडलीय अस्पताल; 7 जिला अस्पतालों में एमसीएच का अपग्रेडेशन और सुदृढ़ीकरण एवं 58 नई एम्बुलेंस की खरीद हेतु वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण

59. रोजगार क्षमता में सुधार के लिए परामर्श और कौशल प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। मैं प्रशिक्षण और कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 179 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं। हम इस संबंध में पंजाब हुनर विकास योजना शुरू कर रहे हैं और सी-पाइट प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 46 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य

60. आप सरकार से पहले, राज्य के नौकरी प्रदाता उद्योगपतियों के पास औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देने के लिए कोई मंच नहीं था। हमारी सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्व को समझती है और पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना करती है। पंजाब भर के व्यापारियों के साथ सीधे संपर्क की सुविधा के लिए "सरकार व्यापार मिलनी" की शुरूआत आप सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में इन मिलनी प्रोग्रामों ने उद्यमियों को अपनी चिंताओं को सामने रखने और संयुक्त रूप से उनके समाधान खोजने का अवसर प्रदान किया है।

61. हमारे एमएसएमई हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने एक नए एमएसएमई विंग की स्थापना की है। यह विंग हमारे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उनके विस्तार और नवाचार के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। इस कदम से लगभग 8 लाख एमएसएमई को लाभ होने की उम्मीद है।

62. हमारी सरकार द्वारा ईज़ आफ़ डुइंग बिज़नेस (ईओडीबी) को और बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट (आईपीबीएफ) पोर्टल को मजबूत किया गया है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से दस हजार से अधिक इकाइयों को नियामक मंजूरी प्रदान की गई है, एक लाख से अधिक इकाइयों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक प्राजेक्टों को तेजी से और आसानी से मंजूरी मिलने को सुनिश्चित करने के लिए सेल-डीड के पंजीकरण के लिए 'ग्रीन स्टांप' पेपर पेश किया है।

63. मैं वित्त वर्ष 2024-25 में हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए सब्सिडी वाली बिजली सहित 3,367 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं। इस के साथ ही, राज्य के उद्योगों को अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए शुरुआत में 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

शासन सुधार

अध्यक्ष महोदय,

64. सरदार भगवंत सिंह मान जी के दृष्टिकोण के तहत आप सरकार ने पंजाब के निवासियों को उनके दरवाजे पर 43 सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी (डीएसडी)

शुरू की है। अब पंजाबियों को पहले की तरह सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने या परेशानी का सामना करने की आवश्यकता नहीं है।

65. एक अन्य सुशासन पहल में, कालेजों में एक केंद्रीकृत दाखिला पोर्टल लागू किया गया है जिसके माध्यम से 2023-24 में लगभग 300 कॉलेजों में लगभग 1.5 लाख छात्रों को दाखिला दिया गया। हमारी सरकार ने एक सिंगल एकीकृत मंच भी पेश किया है जिसके तहत नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन/मोबाइल ऐप/कॉल सेंटर और सेवा केंद्रों के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त हुईं 2.23 लाख शिकायतों में से अब तक 2.03 लाख का समाधान किया जा चुका है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

66. खाद्य क्षेत्र में सुशासन को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आवंटन में पारदर्शिता लाने और व्यय को अनुकूलित करने के लिए, आप सरकार ने मंडियों को चावल मिलों के साथ ऑनलाइन जोड़ने की शुरुआत की है। चावल के उत्पादन के साथ चावल मिलों की बिजली खपत की निगरानी करने और पीडीएस चावल की फर्जी खरीद और रीसाइक्लिंग पर अंकुश लगाने के लिए अनाज-खरीद पोर्टल का एकीकरण पीएसपीसीएल पोर्टल के साथ किया गया है। विभाग में विभिन्न पहल करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1,072 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

67. इसके अलावा, गेहूं और धान/चावल ढोने वाले वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है और मंडियों से भंडारण पुआंइटों/मिलों तक गेहूं/धान ढोने के लिए अनाज खरीद पोर्टल के माध्यम से सभी गेट पास ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं।

68. हमारी सरकार द्वारा मार्कफेड के माध्यम से लगभग 800 मॉडल उचित मूल्य दुकानें (एमएफपीएस) स्थापित की जा रही हैं। और एनएफएसए गेहूं का आटा पीस कर, लाभार्थियों को घर-घर वितरण के लिए इसकी पैकेजिंग करेगी। इससे हमारे गरीबों को समय बचाने, राशन डिपो पर लंबी कतारों से बचने और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी के लिए "घर घर मुफ्त राशन योजना" भी शुरू की है और वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन

69. इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रभावित आबादी को निकालने, आश्रय प्रदान करने और भोजन और चिकित्सा सहायता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल और व्यापक राहत प्रयासों की आवश्यकता हुई। हमारी सरकार ने फसल क्षति, मानव जीवन की हानि, पशुधन की हानि और आवासों की क्षति सहित विभिन्न नुकसानों को कवर करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 490 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। इसके अलावा, इस विभाग की विविध पहलों का समर्थन करने के लिए, मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 1,573 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं।

70. राज्य के 13,004 गांवों में से, 39,134 मुसावी शीट्स वाले 6,670 गांवों के नक्शों को डिजिटाईज़ किया गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्ष में सभी मुसावियों को डिजिटाईज़ करना है ताकि एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा सके। इसके अलावा, राज्य में तहसील/उप-तहसील स्तर पर 178 फर्द केंद्र संचालित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश गांवों का राजस्व रिकॉर्ड पहले ही डिजिटाईज़ हो चुका है।

71. चालू वित्तीय वर्ष में, कुशल संचालन को सुविधाजनक बनाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासनिक परिसरों, तहसीलों, उप-तहसीलों और उप-विभागीय परिसरों के निर्माण और मरम्मत के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

एनआरआई मामले

72. आप सरकार हमारे एनआरआई भाइयों और बहनों, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था और समाज में विशेष भूमिका निभाते हैं, के साथ लगातार संपर्क में रहती है। हमने 2023-24 में पठानकोट, एसबीएस नगर, फिरोजपुर और संगरूर में 4 एनआरआई मिलनी कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आगामी वर्ष में भी ऐसे कार्यक्रम करना जारी रखेंगे।

73. एनआरआई मामलों के लिए सुशासन पहलों का विस्तार करते हुए, हमारी सरकार ने विदेशों में रहने वाले पंजाबियों को ई-सनद पोर्टल के माध्यम से विदेशी दूतावासों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिहस्ताक्षर/सत्यापन करने में सक्षम बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एनआरआई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जो उन्हें शिकायतें दर्ज करने, यदि कोई हों, और सुझाव देने के लिए एक प्लेटफ़ार्म प्रदान करता है।

रक्षा सेवाएँ

74. हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व सैनिकों, युद्ध-विधवाओं, विश्व युद्ध के दिग्गजों, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों की भलाई के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसा कि पिछले बजट में एक्स-ग्रेशिया ग्रांट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का वादा किया गया था, हमारी ओर से चालू साल में शहीद सैनिकों के परिवारों को यह एक्स-ग्रेशिया ग्रांट जारी कर दी गई है।

75. इसके अलावा, युद्ध विधवाओं के लिए पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह और ब्लू-स्टार प्रभावित धर्मी फौजी की सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। साथ ही युद्ध जागीरों के लिए पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष किया जा रहा है। रक्षा कर्मियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखने के लिए, मैं कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 77 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले

माननीय अध्यक्ष महोदय,

76. हमारे राज्य की अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन और ट्रैवल मार्ट 2023 एस.ए.एस नगर (मोहाली) में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, पंजाब की जीवंत संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न जिलों में 22 मेलों का आयोजन किया गया है। अमृतसर में "रंगला पंजाब" मेला हमारी संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में भी काम करता है। ये सभी आयोजन पंजाब को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प का प्रतीक हैं।

77. परशाद योजना के तहत श्री चमकौर साहिब में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा, एंग्लो-सिख युद्ध सर्किट विकसित करने का काम पहले से ही चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। साथ ही, भारतीय संस्कृति में पगड़ी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला श्री आनंदपुर साहिब में पगड़ी संग्रहालय बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

78. पंजाब को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 166 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूं,

जिसमें विभिन्न स्मारकों के निर्माण, रखरखाव और संरक्षण के लिए 30 करोड़ रुपये का विशेष खर्च और पंजाब राज्य में पर्यटन की ब्रांडिंग के लिए 30 करोड़ रुपये का विशेष परिव्यय शामिल है। ।

79. इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, 25 करोड़ रुपये की लागत से "विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों / पंजाब के बीरों में इकोटूरिज्म गतिविधियां" नामक एक प्राजेक्ट तैयार किया गया है और इसे आने वाले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा और इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में उपयुक्त आवंटन किया गया है। पठानकोट में रणजीत सागर बांध को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पहले से ही अलग से प्रयास चल रहे हैं।

गृह मामले, न्याय और जेलें

अध्यक्ष महोदय,

80. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए उनकी कानून प्रवर्तन पहलों का समर्थन करने के लिए 10,635 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च का प्रावधान किया गया है।

81. मैं "सड़क सुरक्षा फ़ोर्स" बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पुलिस बल को सर्वोत्तम टोयोटा हिलक्स वाहन मिले हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले एक बेजोड़ उपलब्धि है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुलिस कर्मियों के लिए पिछले पांच वर्षों में खरीदे गए 1,993 वाहनों में से 1,396 वाहन पिछले दो वर्षों में खरीदे गए हैं।

82. मैं साझा करना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी करके कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। यह प्रयोगशाला परिष्कृत अपराध

विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगी और कानून प्रवर्तन में आने वाली उभरती चुनौतियों का समाधान करेगी।

83. हम अगले वित्तीय वर्ष में पुलिस प्रशासन से संबंधित अपनी सुधारात्मक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे।

84. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 827 सब-इंसपेक्टर, 787 हेड कांस्टेबल, 144 सिविलियन कर्मचारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और सीसीटीएनएस प्राजेक्ट के सर्वोत्तम लागूकरन के लिए 4,100 टैब और 4,300 फोन खरीदे और जांच अधिकारियों को वितरित किए गए हैं, जिससे प्रभावी जांच और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से परस्पर नागरिक बातचीत की सुविधा मिल सके।

सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय

85. सामाजिक कल्याण पहल करने, एक न्यायसंगत, न्यायसंगत और दयालु समाज के विकास को बढ़ावा देने की आप सरकार की प्रतिबद्धता को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के समर्थन में देखा जा सकता है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 9,388 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

86. सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 5,925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, पोषण अभियान; आशीर्वाद योजना; सुगम्य भारत अभियान; प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 1,053 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।

87. हमारी सरकार हमारे एससी/बीसी/अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों और समाज के सभी दबे-कुचले वर्गों के साथ खड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जाति

उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 13,844 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 35% है।

बुनियादी ढांचा

सड़कें और पुल

88. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमारी सरकार ने पीएमजीएसवाई -III के तहत 805 किलोमीटर सड़कों और चार पुलों का निर्माण पूरा किया है, जिस पर 400 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में पीएमजीएसवाई-III के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएच (मूल कार्य) के तहत 177 करोड़ रुपये की लागत से 31 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया गया है। सीआरआईएफ योजना के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत से 22 किलोमीटर सड़क का अपग्रेडेशन किया गया है। राज्य योजना के तहत 199 करोड़ रुपये की लागत से 176 किलोमीटर सड़क का अपग्रेडेशन कार्य पूरा किया गया है। मैं कनेक्टिविटी की धमनियों यानी सड़कों और पुलों के लिए 2,695 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं।

89. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि सिख धर्म में इसके गहन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बावजूद, श्री आनंदपुर साहिब में, आजादी के 75 साल बाद भी कई गांवों में अभी भी उचित कनेक्टिविटी का अभाव है। इन गांवों के निवासियों की यात्रा में आसानी और उचित कनेक्टिविटी के लिए, खेड़ा कल्मोट और भल्लाडी एवं बेला ध्यानी और अजौली के बीच पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

90. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब ने ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में सफलतापूर्वक पूर्ण कवरेज हासिल कर लिया है। पंजाब ने पूरे देश भर में "हर घर जल" योजना में 5वां रैंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। पानी की गुणवत्ता और कमी से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए 2024-25 लगभग 2,200 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 बड़ी बहु-ग्राम सतह जल आपूर्ति योजनाएं पूरी होने की आशा है। इस के तहत 1,706 गांवों को कवर किया जाएगा।

91. सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के प्रयास में, आईआईटी मद्रास की एडसार्पशन तकनीक का उपयोग करने वाले आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट (एआईआरपी) विभिन्न जिलों के 685 गांवों में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 170 सीमावर्ती गांवों में घरेलू प्यूरीफायर और सामुदायिक जल शोधन प्लांट वितरित किए और लगाए गए हैं, जिस पर कुल 133 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

92. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मौजूदा बुनियादी ढांचे के प्रतिस्थापन और पुनर्वास, और सतही जल आधारित योजना की स्थापना और संवर्द्धन जैसे प्राजेक्टों को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1,549 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

जल संसाधन

93. आप सरकार ने इस साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और लगभग 3,461 किलोमीटर नालों की सफाई के लिए और 68 बाढ़ सुरक्षा प्राजेक्टों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके अतिरिक्त, लगातार बारिश और बाढ़ के पानी के कारण प्रमुख नदियों में आई दरारों भरने के लिए 192 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हमारी नहरों को और मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 2,107 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

94. माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाले माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर, हम एक नए मालवा नहर प्राजेक्ट का प्रस्ताव रखते हैं। इस पहल का लक्ष्य लगभग 1,78,000 एकड़ को कवर करना है, जिससे बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और मुक्तसर जिलों को लाभ होगा। इस प्राजेक्ट का उद्देश्य भूजल पर निर्भरता को कम करना और रबी अवधि के दौरान ब्यास-सतलुज नदी के पानी के कम उपयोग वाले पंजाब के हिस्से को अनुकूलित करना है।

95. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शाहपुर कंडी बांध परियोजना में जल-भरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे 37,173 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के साथ-साथ अपर बड़ी दोआब नहर (यूबीडीसी) प्रणाली के तहत यानी अमृतसर, गुरदासपुर तरन तारन और पठानकोट में 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की गहन सिंचाई क्षमता पैदा होगी। जल विद्युत उत्पादन का बुनियादी ढांचा जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिसकी क्षमता 206 मेगावाट है।

96. हमारी सरकार ने जलमार्गों की लाइनिंग के कार्यों को प्राथमिकता दी है और पूरे राज्य में 80 करोड़ रुपये की राशि के कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में नए प्राजेक्टों- निर्माण/री-मॉडलिंग और लाइनिंग/री-लाइनिंग कार्यों के लिए 143 करोड़ रुपये और राजस्थान और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

स्थानीय सरकार और शहरी विकास

97. मुझे इस बात पर गर्व है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पंजाब ने उत्तरी क्षेत्र में प्रथम रैंक हासिल किया है। 2023-24 के दौरान, 148 यूएलबी में से 79 में पुराने कचरे का निवारण कार्य पूरा हो गया था, 31 मार्च,

2026 तक शेष 69 यूएलबी को हल करने के प्रयास जारी हैं। मैं स्थानीय शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 6,289 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं।

98. अपना स्वयं का पक्का घर न होने वाले वंचित परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से; 225 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 में 30,000 घरों का निर्माण हो चुका है और मैं शेष घरों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 510 करोड़ रुपये के फ़ंड प्रस्ताव रखता हूं।

99. जल आपूर्ति योजनाओं और पर्यावरण कायाकल्प से संबंधित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) के तहत कार्य करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में 394 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के लिए; राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन; पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 538 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

100. नए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूडीआईएफ) के तहत, हम सीवरेज उपचार प्लांटों से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचा प्राजेक्टों को शुरू करने; शहरी पार्क; लैइर वैली; और राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायता से जल आपूर्ति में वृद्धि और पुनर्वास आदि के लिए 322 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखते हैं।

101. इसके अलावा, पंजाब सरकार शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सहयोग कर रही है और जल्द ही जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला शहरों में ई-बसें चलेंगी।

102. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों - जल संसाधन; जल आपूर्ति एवं स्वच्छता; स्थानीय सरकार और जनतक कार्य में पीआईडीबी द्वारा शुरू किए जाने वाले बुनियादी प्राजेक्टों के लिए 900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

103. अध्यक्ष महोदय, आप सरकार बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आजीविका के सृजन के माध्यम से ग्रामीण आबादी के लिए सर्वांगीण विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 3,154 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

104. हमारी सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान को जबरदस्त सफलता मिली है। इसके परिणामस्वरूप, 12,000 एकड़ से अधिक भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई, जिसे बड़े पैमाने पर इसके असली मालिकों अर्थात पंचायतों को सौंप दिया गया है।

105. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए निम्नलिखित आवंटन प्रस्तावित किए जा रहे हैं:

i. मनरेगा: रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 655 करोड़ रुपये;

ii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: 20 करोड़ रुपये;

iii. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 120 करोड़ रुपये; और

iv. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: 20 करोड़ रुपये।

खुदाई

106. हमारी सरकार ने 3 चरणों में कुल 60 सार्वजनिक खनन साइटों का संचालन किया है और इन साइटों से कुल 14.66 लाख मीट्रिक टन रेत 5.50/- रुपये प्रति क्यूबिक फ़ीट के पिट हेड बिक्री मूल्य पर बेची गई है। अगले चरण में, राज्य में जल्द ही अन्य 16 साइटें शुरू होने की उम्मीद है।

107. "कमर्शियल खनन स्थलों" की नीलामी की जा रही है जिसमें 67 खनिज-युक्त स्थलों वाले 40 क्लस्टर शामिल हैं। हम आगामी वर्ष में राज्य में कमर्शियल खनन स्थलों के 100 क्लस्टरों की नीलामी करने का इरादा रखते हैं।

108. क्रशर यूनियनों द्वारा उठाई गई चिंताओं के निवारण के प्रयास में, सरकार ने "पंजाब क्रशर नीति" अधिसूचित की है और क्रशर उद्योग में और सुधार करने के लिए, हम जल्द ही "पब्लिक क्रशर यूनिट्स" नामक एक पहल शुरू करेंगे।

परिवहन

109. "मुख्य मंत्री तीर्थयात्रा" के माध्यम से हम पंजाबियों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की मुफ्त तीर्थयात्रा का अवसर प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये के साथ परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

110. हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है और इसके तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

111. लुधियाना और मोरिंडा में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पहले ही काम करना शुरू कर चुकी है और नए गैर-परिवहन वाहनों को मोटर वाहन कर में 25% तक की छूट प्रदान की जा रही है।

112. मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य की लगभग 11 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाया है, जिसके लिए सरकार द्वारा 450 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और इस सेवा को जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 450 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है।

बिजली

113. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने 540 मेगावाट की क्षमता वाले पूर्व जीवीके गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को खरीद लिया है, जिसका नाम अब श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट है। यह अधिग्रहण 1080 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय रूप से कम लागत पर हासिल किया गया है, जो एक नए थर्मल प्लांट पर आने वाली 8.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की सामान्य लागत के मुकाबले 2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है।

114. हमारी सरकार का ध्यान बिजली के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और हमारे पावरकॉम को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने पर है। कई महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं, जिनमें रोपड़ में एक नए 400 केवी सबस्टेशन का निर्माण, धनांसु, बेहमान जस्सा सिंह में सबस्टेशनों को मजबूत करना है और शेरपुर (लुधियाना) में 220 केवी सबस्टेशन जल्द ही चालू होने वाला है।

115. वर्तमान में 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 7,780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

116. मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पावर सेक्टर के कार्यबल को मजबूत करने के लिए कुल 4,575 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

117. पंजाब के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 6.17 मेगावाट सोलर रूफ टॉप प्लांट, 811 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम और 10,218 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

118. इसके अतिरिक्त, राज्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल है, जैसे 50 मेगावाट नहर शीर्ष परियोजना का विकास; 10,833 सौर स्ट्रीट लाइटों को लगाना; 220 मेगावाट वाले सोलर पावर प्लांट और 20,000 कृषि ऑफ-ग्रिड सोलर पंप आदि। राज्य घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, नगरपालिका, भवन और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

नागरिक उड्डयन

119. मुझे बताना चाहूंगा कि आदमपुर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से एक नया हवाई टर्मिनल, 75 यात्रियों की पिछली पोर्टा केबिन क्षमता को 150 यात्रियों की क्षमता में बदलने का काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे पर सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। हलवारा में शहीद करतार सिंह सराभा हवाई अड्डे से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इन दोनों हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू होने से विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

120. हमारी सरकार के ठोस प्रयासों से, अमृतसर से कुआलालंपुर के लिए दो और मिलान के लिए एक उड़ान शुरू की गई है और बठिंडा से भी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। पंजाब और यूरोपीय देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं।

121. इसके अतिरिक्त, पटियाला एविएशन क्लब और अमृतसर एविएशन क्लब के लिए एक मल्टी-इंजन विमान और दो सिम्युलेटर खरीदे जा रहे हैं। इनका उपयोग उन संभावी पायलटस को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

राजस्व वृद्धि

122. वित्त वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,03,936 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें स्वयं का कर राजस्व 58,900 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय करों का हिस्सा 22,041 करोड़ रुपये और केंद्र से ग्रांट-इन-एड 11,748 करोड़ रुपये आंकी गई है।

123. हमारे अपने कर राजस्व यानी जीएसटी के प्रमुख योगदानकर्ता को बढ़ावा देने के लिए, कराधान विभाग ने कराधान से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए आईआईटी, हैदराबाद के साथ सहयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी कर इंटेलिजेंस युनिट मजबूत हुई है और अनुपालन दर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, हमारी अभिनव योजना "बिल लियाओ नाम पाओ" ने भी अच्छे नतीजे दिए हैं। लगभग 60,000 बिल अपलोड किए गए हैं और 60 लाख रुपये के पुरस्कार वितरित किए गए हैं। राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में राजस्व वृद्धि के कई अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

माननीय अध्यक्ष महोदय,

124. हमारी सरकार हमारे राष्ट्रीय संयोजक के मार्गदर्शन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन पहलों के माध्यम से पंजाब और पंजाबियों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अर्थव्यवस्था और समाज के बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

वतन के जाँ-निसार हैं वतन के काम आएँगे

हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमाँ बनाएँगे

125. अटूट दृढ़ संकल्प और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, हम एक अधिक मजबूत, गतिशील और जोशीला "रंगला पंजाब" बनाने की राह पर अग्रसर हैं।

126. अंत में, मैं वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उनके समर्पण, ईमानदारी और मेहनती कार्य नैतिकता के लिए हार्दिक सराहना करता हूं, जिस ने इस बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

127. मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए इस प्रतिष्ठित सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द